International Journal of Applied Research 2021; 7(8): 37-40

ISSN Print: 2394-7500
ISSN Online: 2394-5869
Impact Factor: 8.4
IJAR 2021; 7(8): 37-40
www.allresearchjournal.com
Received: 05-06-2021
Accepted: 20-07-2021

भावना भट्ट
शोध छात्रा, राजनीति विभाग,
कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल,
उत्तराखण्ड, भारत

Corresponding Author:
भावना भट्ट
शोध छात्रा, राजनीति विभाग,
कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल,
उत्तराखण्ड, भारत

वैश्वीकरण एवं इसके प्रभाव का एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

भावना भट्ट

सारांश
भूमण्डलीकरण, वैश्वीकरण, भूमण्डलीय गांव या अन्तर्राष्ट्रीय बाजार कई नामों से इस शब्द की व्याख्या की गई हैं। इसे अंग्रेजी भाषा में ग्लोबलाइजेशन कहते है। यह शब्द अंग्रेजी भाषा के ग्लोब शब्द से बना है जिसका अर्थ पृथ्वी एवं गोल होता है। इसी का विशेषण ग्लोबल होता है जिसका अर्थ पूरे विश्व को समाहित करना। ग्लोब से बनी हुई क्रिया को संज्ञा रूप में परिवर्तित करने पर इस प्रक्रिया को व्यक्त करने वाला शब्द ग्लोबलाइजेशन है जिसका तात्पर्य ''पूरे विश्व को समाहित करने वाली प्रक्रिया''।

कूटशब्द : राज्य प्रतिबंध, विश्व स्तरीय तंत्र, विक्षेत्रीकरण, बहुराष्ट्रीय कम्पनी, विश्व बैंक, I.M.F., W.T.O. उदारीकरण, निजीकरण।

प्रस्तावनाः
वैश्वीकरण वर्तमान समय में मानव जीवन के प्रत्येक पहलू को प्रभावित कर रहा है, चाहे वह राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक हो, प्रत्येक राष्ट्र किसी ना किसी प्रकार से इसमें जुड़ा हुआ हैं यदि कोई राष्ट्र इससे अलग रहने की कोशिश करता भी हैं तो वह अपना अहित ही करेगा, क्योंकि कोई भी राष्ट्र सम्पूर्ण नहीं है। प्रत्येक राष्ट्र किसी न किसी साधन से वंचित है, वो चाहे तकनीकी हो कच्चा माल हो या अपनी अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति हो। आज के युग में कोई भी राष्ट्र वैश्वीकरण के प्रभाव से अछूता नहीं है। इसके अंतर्गत एक राष्ट्र की स्थिति के आकलन से संपूर्ण विश्व की स्थिति का आकलन किया जा सकता है। प्रस्तुत शोध पत्र में वैश्वीकरण के प्रभाव का एक विस्तृत अध्ययन प्रस्तुत किया गया है।

शोध विधि एवं क्षेत्र
प्रस्तुत शोध पत्र में वैश्वीकरण एवं इसके प्रभाव का एक विश्लेषणात्मक एवं विवरणात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है जो प्रस्तुत शोध पत्र का मुख्य उद्देश्य है। प्रस्तुत शोध पत्र में इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विश्लेषणात्मक एवं विवरणात्मक शोध प्रविधि का प्रयोग किया गया है।
वैश्वीकरण का अर्थ बताते हुए 'टाम जी पामर' कहते है कि ''सीमाओं के पार विनिमय पर राज्य प्रतिबंधों का ह्रास या विलोपन और इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न हुआ उत्पादन और विनिमय का तीव्र एकीकृत और जटिल विश्व स्तरीय तंत्र''। (विकीपिडिया.IN.WWW), गिडेन्स का मानना है कि वैश्वीकरण को उन विश्वव्यापी सामाजिक रिश्तों के तीव्र होने के रूप में देखा जा सकता है जिनसे एक–दूसरे से दूर स्थित क्षेत्रों में होने वाली स्थानीय घटनाओं को सैकड़ों मील की दूर की घटनाओं से प्रभावित करते हैं।'' रोलेन्ड रविडसन, ''वे वैश्वीकरण की परिभाषा करते हुए इसे विश्व का सिकुड़ना और समग्रता में विश्व की चेतना का तीव्र होना बताया'' मार्टिन एलब्रो, ''वैश्वीकरण का मतलब उन सभी प्रक्रियाओं से है जिनके माध्यम से विश्व का जन समुदाय एकल विश्व समाज में समाहित हो जाता है।''
स्टिग्लिटज का मानना है कि ''वैश्वीकरण दुनिया के विभिन्न देशों और लोगों का घनिष्ठ समन्वय है जो परिवहन एवं संचार की लागतों में लाई गयी भारी कमी के कारण हुआ है और इसके फलस्वरूप वस्तुओं तथा सेवाओं के प्रवाहों में कृत्रिम रूकावटें समाप्त की गई हैं और एक कम सीमा तक अपनी सीमा के परे लोगों का आना–जाना बढ़ा है।'' जगदीश भगवती के शब्दों में ''आर्थिक'' वैश्वीकरण में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं को अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं में जोड़ने की प्रक्रिया समाविष्ट है। यह व्यापार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (निगमों या बहुराष्ट्रीय उद्यमों) अल्पकालीन प्रवाह है और तकनीकी प्रवाह द्वारा सम्पन्न किया जाता है।'' वही डॉ विमल जालान के ''अनुसार भूण्डलीकरण शब्द का प्रयोग कई तरह से हुआ है, एक अर्थ तो शाब्दिक है कि अब राष्ट्रों के बीच भौगोलिक दूरी बेमानी हो चुकी है, दुनिया काफी छोटी हो चुकी है और कोई भी देश अपना नुकसान करके ही शेष विश्व से खुद को

अलग–अलग रख सकता है, भूमण्डलीकरण का दूसरा अर्थ ठीक उल्टा निकाला जा रहा है इसके अनुसार यह देशी हितों की जगह दूसरे देशों और बहुराष्ट्रीय निगमों के हितों को ऊपर रखने वाले नीतिगत बदलाव का नाम है।''

भारतीय पक्ष में वैश्वीकरण की बात की जाती है तो इसकी नींव स्वतंत्रता से पूर्व ही हमारी संस्कृति में विराजमान थी जिसे हम (वसुधैव कुटुम्बकम) कहते हैं जिसका तात्पर्य यह हैं, समस्त पृथ्वी को एक परिवार के रूप में मानते थे पर आज के युग में परिवार या वैश्विक ग्राम अपने निजी हितों पर आधारित हैं, जिसमें विभिन्न बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ, निगम एवं अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्थाएं हैं जो विश्व संचालन में अपनी अहम भूमिका निभा रहें हैं। साधारण शब्दों में भूमंडलीकरण का अर्थ है देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत (Integrate) करना है। भूमण्डलीकरण की अर्थ एवं परिभाषा से स्पष्ट है कि यह राष्ट्रों की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनैतिक सभी पक्षों को प्रभावित करता है। भारतीय विदेश नीति की बात की जाये तो वह भी कही न कही इसके प्रभाव से अछूता नहीं है जैसे जैसे विश्व धरातल में परिवर्तन देखे गये वैसे वैसे राष्ट्रीय विदेश नीति में परिवर्तन देखा गया। नेहरू के समय भारत तटस्थता और गुटनिरपेक्षता को अत्यधिक महत्व देता था तो श्रीमती इन्दिरा गांधी के समय भारत ने सोवियत संघ से सन्धि करना उचित समझा, जनता शासन में असली गुटनिरपेक्षता पर जोर दिया जाने लगा तो राजीव गांधी ने श्रीलंका में भारतीय शान्ति सेना को भेजकर विदेश नीति को नवीन आयाम प्रदान किया। पी0वी0 नरसिम्हां राव ने नैतिकता तथा मूल्यों पर आधारित नीति पर अधिक बल न देकर आर्थिक पहलू पर अधिक ध्यान देने की चेष्टा की इसकी पृष्ठभूमि में निर्विवादतः वैश्वीकरण का परिप्रेक्ष्य रहा है।

भारतीय परिप्रेक्ष्य में इसका तात्पर्य है विदेशी कंपनियों को भारत की विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में निवेश करने की अनुमति देकर अर्थव्यवस्था को विदेशी पूँजी को रियायते दी गई थी, और बहुत से क्षेत्रों में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के प्रवेश की आज्ञा प्रदान कर दी गई जहा पहले अनुमति नही थी विदेशी विनिमय नियमन अधिनिययम को कड़ाई से लागू नहीं किया, परन्तु भमंडलीकरण की प्रक्रिया में तेजी भारत सरकार द्वारा जुलाई 1991 में लागू की गई (नई आर्थिक नीति के परिणामस्वरूप) आई जो अन्तर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के दबाव के कारण अपनाई गई थी, भारत के समस्त राजनीतिक दलों का इस आर्थिक सुधारों के पक्ष में एकमत थे। ये प्रमुख दल, जनता दल, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, सी0पी0आई0(एम) समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, डी0एम0के0 एवं ए0डी0एम0के0 सभी सरकारों वाले राज्यों में विनियोग बढ़ाने के लिए विदेशी पूँजी पर आश्रित रहते हैं। अतः देश के आर्थिक विकास के लिए आर्थिक सुधारों को क्रियान्वित करने के सम्बन्ध में सभी दलों एकमत हो चुके थे। इस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री– च्ण्टण् नरसिम्हा राव एवं वित्त मंत्री डॉ0 मनमोहनन सिंह जिनके नेतृत्व में भारत में वैश्वीकरण की नीतियों का प्रारम्भ हुआ जिन्हें L.P.G. के नाम से भी जाना जाता हैं जिनको उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण के नाम से जाना जाता है।

वैश्वीकरण के अर्थ एवं परिभाषा के स्पष्ट हो जाने के पश्चात इसके संक्षिप्त इतिहास को जानना भी अनिवार्य हो जाता है आज विश्व सम्प्रदाय में वैश्वीकरण को समझना बहुत पैचीदा होता नजर आ रहा है। कई लेखों में इसकी व्याख्या दिन–प्रतिदिन समझनी मुश्किल होती जा रही हैं, जिसे समझने के लिए अनगिनत शब्द खर्च किये जा चुके हैं यह यथार्थ होते हुए भी आभासी है। यह एक ऐसी साइबर यात्रा है, जिसकी दुनिया इंटरनेट में कैद होने के बाद भी निराकार होकर पकड़ से बाहर चली गयी है। भूमंडलीकरण को समझने की योजना के अंतर्गत सबसे बड़ा खतरा यह भी है जब तक हम उसे समझने का ठोस सिद्धांत एवं निमय निर्मित करे तब तक वह हमें पूरी तरह बदल चुका होगा आर्थिक स्थिति वह नहीं होगी जिसमें हमने जन्म लिया था सांस्कृतिक परिवेश की शक्ल वह नहीं होगी जिसमें हमारे जीवन–मूल्यों की बुनियाद पड़ी थी और हमारी राजनीतिक व्याख्या का मर्म रूप ले चुका होगा जिसके खिलाफ हमने उसे स्थापित करा था। आज विश्व सम्प्रदाय में भूमंडलीकरण एक बहुत बड़ी घटना है जो सब परिवर्तन कर रही हैं। सारी परिस्थितियों को अपने पक्ष में ढालते हुए उसके प्रति विरोधियों की प्रतिक्रिया को परिवर्तन कर यह महसूस होता है जो प्रारम्भ में भूमंडलीकरण के खिलाफ लगता है वही अंतिम विश्लेषण में उसकी संरचनाओं की मदद करता मिलता है भूमंडलीकरण के कारण ना सिर्फ सत्ता में परिवर्तन आया हैं बल्कि विपक्ष के तौर तरीके में बहुत बड़ा बदलाव आया है। दरअसल, भूमंडलीकरण उस सफर का नाम है जो 19 वीं सदी के 1वें दशक में आधुनिकता द्वारा प्रारम्भ हुआ था, जिस आधुनिकता को विभिन्न परिवर्तनो का वाहक मानते हुए प्रसंन्सा से नवाजा गया, कही ना कही वह भूमंडलीकरण, का अग्रपंक्ति भी है। जब तक यह अपने पूर्ण उत्कर्ष में नहीं आया था तब तक विविधता एवं बहुलता को आधार मानने वाले विचारक किस्म–किस्म की आधुनिकता का प्रचार कर रहे थे इस चिंतन के दौरान आधुनिकता की वह प्रवृत्ति छिपी थी जो सभी सभ्यताओं एवं संस्कृतियों को एक साँचे में पिरोनी की वकालत करती है। आधुनिकता ने सवा सौ साल से ज्यादा लंबे समय में सत्ता की ग्लोबल संरचनाओं को हमेशा जीवंत रखा ताकि राष्ट्रीय सीमाओं के भीतर रहकर कार्य करने को मजबूर ना होना पड़े। इसकी सबसे प्रभावशाली और ठोस मिसाल उसने पूँजी और उसकी गतिशीलता के रूप में प्रस्तुत की।

वैश्वीकरण को यदि आधुनिकता के आर्थिक पक्ष से देखा जाए तो यह अपने प्रारम्भ काल के पचास वर्षो में काफी उन्नति करता हुआ नजर आया। 1870–1914 के बीच के इस समय को उन्मुक्त बाजार या वाणिज्य युग के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इस समय पूँजी एवं श्रम के आवागमन में कोई रोक नहीं थी कोई भी कही भी बस सकता था। नागरिकता आसानी से प्राप्त हो जाती थी। सरकार द्वारा बाजार में नियंत्रण ना के बराबर था। टेलीग्राफ, रेलवे एवं जहाजरानी या इस कार्य संचालन में मुख्य भूमिका निभा रहे थे। 19वीं सदी में शुरू हुई इस परिघटना में एक महाशक्ति के रूप में ब्रिटेन मौजूद था जो मुद्रा के रूप में पाउंड–स्टलिंग का प्रतिनिधित्व कर रहा था उस समय तार, रेलवे एवं पानी के जहाज की संचार एवं परिवहन क्रांति द्वारा समस्त विश्व सम्प्रदायों की दूरी कम करी जा रही थी। लेकिन 90 के दशक में जैसे ही यह विचार पूर्णरूप से प्रकट हुआ वैसे ही यह हकीकत सामने आ गयी कि यूरोपीय ज्ञानोदय की कोख में जन्में आधुनिकता के विचार में कही ना कही विस्वाद का पहलू विराजमान था। आधुनिकतावाद हमेशा एक 'ग्लोबल प्रणाली' ग्लोबल नागरिक और ग्लोबल राजनीति रचने की कल्पना से प्रेरित रहे हैं राष्ट्रीय, क्षेत्रीय एवं सांस्कृतिक सीमाएं आधुनिकता के इस आयाम के ऊपर कभी हावी नहीं हुई। भूमंडलीकरण के इस आवरण से मनुष्य समुदाय लाभान्वित हो रहा था, लेकिन असमान रूप से यूरोपीय राष्ट्रों को लाभ प्राप्त हो रहा था लेकिन उसका बड़ा हिस्सा उपनिवेशवादी देश हड़प जाते थे। यही राष्ट्र पूँजी के निर्यातक एवं जिंसो के आयातक थे। दक्षिणी और पूर्वी यूरोप समृद्धि की दौड़ में पीछे होते जा रहे थे। एशिया, अफ्रीका और लातीनी अमेरिका के उपनिवेशों की हालत खराब थी। यही समय था भारत, चीन और इंडोनेशिया जैसे देशों का अ–उद्योगीकरण हुआ और वे अविकसित की श्रेणी में आते चले गये। इन राष्ट्रों की व्यवस्था मुक्त व्यापार पर आधारित थी और इन्हें विदेशी निवेश का बड़ा हिस्सा मिल रहा था। इसके विपरीत संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में वहा की श्वेत जनता को लाभ पहुँचाने के लिए उद्योगीकरण के हालात बनाये गये। कारखाना

आधारित उत्पादन में सीधा पूँजी निवेश हुआ, प्रौद्योगिकीय और प्रबंधकीय क्षमताओं का विकास हुआ। मुख्य बात यह थी कि इस समय भारत, चीन और इंडोनेशिया जैसे देश सबसे ज्यादा विदेशी निवेश प्राप्त कर रहे थे, लेकिन इन राष्ट्रों का विकास नहीं हुआ और अमेरिका अपने विकास को बढ़ाता चला गया। सम्पन्न एवं विपन्न राष्ट्रों के मध्य आमदनी अंतराल 1:1 से बढ़कर 11:9 हो गया। वास्तव में भूमंडलीकरण विषमतापूर्ण पाया गया।

सैन्यवाद, साम्राज्यवाद, नस्लवाद और इजरिदारियों ने पूँजी को बड़ी खुदगर्जो के साथ मिला एक विशाल अजगर का निर्माण करा जिसने कमजोर एवं गरीब राष्ट्रों को तो सताया ही वही इसके प्रभाव से शक्तिशाली राष्ट्र भी प्रभावित रहे। 'जान मेनाडिकींस' ने 1919 में माना कि 1914 में खत्म हुआ आर्थिक प्रगति का वह दौर बेमिसाल तौर पर असाधारण था। पूरे विश्व सम्प्रदाय में घटित प्रथम विश्व युद्ध की घटना ने भूमंडलीकरण की धारणा को ही बदल दिया। मार्क्सवादी एवं राष्ट्रीय क्रांतियों के युग ने साम्राज्य के विचार को पीछे धकेल दिया। उस समय पूँजी एवं श्रम की नियामक सरहदें हो गयीं।

इस विभिषिका के परिणामस्वरूप पूँजी एवं श्रम का आवागमन कठिन हो गया। उसके कुछ समय पश्चात द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारम्भ हो गया। विश्व सम्प्रदाय दो भिन्न विचारधारा का प्रतिनिधित्व कर रहा था। प्रथम पूँजीवाद बनाम समाजवाद, दोनों का ही सपना अपने–अपने तरह के भूमंडलीकरण से जुड़ा था आधुनिकता के गैर–पूँजीवादियों का मानना था कि वे पूँजीवाद के मुकाबले बेहतर किस्म का लोकतंत्र, अधिक समतामूलक अर्थव्यवस्था प्रत्येक राष्ट्र को अपने विकास का मौका मिलने का दावा किया जा रहा था। इस दूसरे भूमंडलीकरण को अंतर्राष्ट्रवाद कहा गया। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रवाद जिसके केन्द्र में बाजार ना होकर एक मानवीय समझौता दिखाई पड़ता था इसके केन्द्र में सोवियत संघ एक गैर पूँजीवादी महाशक्ति के रूप में मौजूद था। यूरोप के कम विकसित हिस्से के साथ–साथ उसने एशिया और लातीनी अमेरिका के नवस्वतंत्र राष्ट्रों के साथ आर्थिक–राजनीतिक, सामाजिक संधियां करके सत्तर के दशक तक पूँजीवादी भूमंडलीकरण के साथ प्रतियोगिता करने का भरसक प्रयास किया गया।

इस दौरान पूँजीवादी भूमंडलीकरण के पुराने और नये नियोजक ब्रेटन वुडस समझौता के जरिये अपने सपनों को पूर्ण करने के भरसक प्रयास करते रहे। 1944 में न्यू हैम्पशायर की पहाड़ी सैरगाह ब्रेटन वुडस में बैठकर ब्रेटन एवं अमेरिका द्वारा एक संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का ताना–बाना तैयार किया गया और राष्ट्रीय मुद्राओं को अमेरिकी डालर से निर्धारित विनिमय दर के आधार पर जोड़ दिया गया और जरूरत पे सोने में मुनाफे का अधिकार दिया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक की स्थापना की गयी। पूँजीवादी भूमंडलीकरण के केन्द्र में औपचारिक रूप से ब्रिटेन के स्थान पर अमेरिका आ चुका था। पाउंड की जगह डालर ने ले ली।

इस नई मौद्रिक व्यवस्था का उद्देश्य आर्थिक राष्ट्रवाद की रोकथाम तथा बढ़ते हुए अन्तर्राष्ट्रीय मेलजोल के सन्दर्भ में मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना था। उत्तर–ब्रेटन वुडस युग में विश्व अर्थव्यवस्था साझे बाजार से शुरू होकर यूरोपियन संघ के रूप में परिवर्तित हो गई, अन्य कई क्षेत्रीय–आर्थिक तन्त्र के उदय ने अन्तर्राष्ट्रीय फर्मो के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया 21 वर्षो के बाद 15 अगस्त 1971 को अमरीकी राष्ट्रपति निक्सन ने (ब्रेटनवुड्स व्यवस्था के अन्त की घोषणा कर दी साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका अब अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक व्यवस्था के नियमों एवं प्रक्रियाओं का अनुपालन नही करेगा। तेल संकट, बाजार व्यवस्था का बढ़ता असन्तुलन और औद्योगिक देशों की विकास दर में ह्रास ये ही वे कारण थे जिनसे 1990 के दशक में भूमण्डलीकरण की शुरूआत हुई।

महत्व :– वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसने मनुष्य जीवन के प्रत्येक पहलू जीवन एश्वर्य, शासन व्यवस्था और अभिज्ञान सभी के नवीन प्रतिरूपों का निर्माण किया है। वैश्वीकरण को समस्त विश्व सम्प्रदाय की बढ़ती (अन्योन्याश्रित) के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।

स्कॉलटे इसे ''लोगों के बीच अधिप्रादेशिक सम्बन्धों का विकास मानते हैं। संयुक्त राष्ट्र, I.M.F. और W.T.O. जैसे अन्तः सरकारी संस्थाओं की बढ़ती भूमिका वैश्वीकरण की प्रक्रिया को तेज कर रही है। आंतरिक और बाहरी मामलों में परम्परागत अन्तर अब अधिक नहीं रह गए हैं। क्योंकि आज इस भू–सम्प्रदाय में घटित कोई घटना मीलों दूर तक अपना प्रभाव छोड़ रही हैं। उदाहरण–अमेरिका में सूचना प्रौद्योगिकी (IT) क्षेत्रों में मध्यावकाश ने भारत में सॉफ्टवेयर इन्जीनियरों के कैरियर को प्रभावित किया। अतः यह महसूस किया जाने लगा कि राज्य द्वारा अपनी राष्ट्रीय नीतियों से अपना प्रभुत्व कम होता नजर आ रहा है। आज अन्तः सरकारी संगठन अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहें हैं। कैनिची ओहमेह के अनसुार राष्ट्र–राज्यों की सीमाएँ सिकुड़ती जा रही है और चार (I I I I S) investment, industry, information and individual] अर्थात निवेश, उद्योग, सूचना और व्यक्ति के कारण दिन–व–दिन यह प्रासंगिक होती जा रही है जिसने सभी घटनाओं के प्रति राज्य को प्रेक्षक या दर्शक बना दिया है। उन्नत तकनीक, एक उदारीकृत बाजार, तुलनात्मक रूप से स्थिर राजनीतिक संगठन आदि ने वैश्वीकरण के विकास में महत्वपूर्ण योग दिया है। वैश्वीकरण एक बहुआयामी प्रक्रिया है, प्रत्येक क्षेत्र के विचारक इसे अपनी दृष्टि से देखते हैं।

वैश्वीकरण एवं प्रभाव :–

वैश्वीकरण जिस प्रकार पूरे विश्व सम्प्रदाय में चर्चा का एक विषय बना हैं। इसके विकास की बात करे तो यह हमें कई वर्षो पूर्व बहुराष्ट्रीय निगमों एवं अनुदारवादी आन्दोलन में देखने को मिलता हैं। जो मुक्त व्यापार की माँग करते थे। जिसके अन्तर्गत विकास दर में वृद्धि एवं लोकतंत्र सुदृढ़ होने की बात की जाती है। यह माँग पूर्वी सम्प्रदाय द्वारा पश्चिमी सम्प्रदाय से की जाती है। यू0एन0डी0पी0 की 'हयूमैन डवलेपमेंट रिपोर्ट में' भूमण्डलीकरण के तीन कर्ताओं का उल्लेख किया गया है 'प्रथम' है विश्व व्यापार संगठन' जो सदस्य देशों की राष्ट्रीय सरकारों के ऊपर अपना वर्चस्व एवं प्रभुत्व रखता है, द्वितीयकर्ता है बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ जिनकी आर्थिक क्षमता अनेक राष्ट्र राज्यों की कुछ सम्पत्ति से ज्यादा है तथा 'तृतीय' कर्ता है अन्तर्राष्ट्रीय गैर–सरकी संगठन जिनका तानाबाना समूचे विश्व में फैला हुआ है ये तीनों मिलकर वैश्वीकरण को अपनी इच्छा अनुसार दिशा प्रदान करते है।

विकसित देश एवं वैश्वीकरण :–

वैश्वीकरण के प्रभाव की बात विकसित राष्ट्रों के लिए करी जाए तो लाभजन्य ही मानी जाएगी क्योंकि वैश्वीकरण का विचार उदारवादी मान्यताओं के अनुरूप ही होता हैं। अतः यह राष्ट्र अपने औपनिवेशिक मनसूबों को पूर्ण करते हैं। जिस प्रकार पूर्व का उपनिवेशवाद देश के राजनीतिक व्यवस्था में पूर्ण नियंत्रण कर देश के राजनीतिक व्यवस्था में पूर्ण नियंत्रण कर देश स्वसंचालन करते थे। आज यह प्रयास आर्थिक गतिविधियों से संचालित हो रहा है। यह मुक्त व्यापार एवं बाजार की वकालत करता है। जिसके अन्तर्गत यह विकासशील एंव अविकसित राष्ट्रों के प्राकृतिक साधनों का निर्ममता से दोहन कर वातावरणीय असन्तुलन पैदा तो करते ही करते है। वहीं इन राष्ट्रों पर उच्च ब्याज दरें लाद दी जाती है जिससे यह आर्थिक क्षेत्र के साथ–साथ, राजनीतिक नीति निर्माण में भी अपना स्पष्ट दबाव बनाने का प्रयास करते है। अतः स्पष्ट है कि वैश्वीकरण

विकासशील एवं अविकसित राष्ट्रों की तुलना में विकसील राष्ट्रों के हितों कें अनुकूल हैं।

विकासशील/वैश्वीकरण :–

विकासशील राष्ट्रों में प्रभाव की बात की जाए तो प्रारम्भ में सभी विकासशील राष्ट्र इसके बाहरी नीतियों से प्रभावित हो जाते है। एवं इसके आन्तरिक साम्राज्यवादी जाल में फंस जाते है। अतः प्रारम्भ में तो यह लाभ जन्य महसूस होती है क्योंकि बाहरी पूँजी निवेश से देश के भीतर आय का सृजन होता है। कच्चा माल के निर्यात से आय का सृजन होता है। एवं तकनीकी विकास देखने को मिलता है। परन्तु लाभ की तुलना नुकसान अधिक देखने को मिलता है। कच्चे माल के दोहन से प्राकृतिक सम्पत्ति का हनन एवं पर्यावरणीय असन्तुलन देखने को मिलता हैं। वहीं तकनीकी विकास की बात करी जाय तो यह तकनीकी वे राष्ट्र (विकसित देश) कई वर्षो पूर्व प्रयोग से छोड़ चुके होते है। जिस निवेश की बात की जाती हैं, वह निवेश इतनी बड़ी मात्रा में होता है कि इन देशों का बजट अधिकांशतः ऋण के रूप में चला जाता हैं एवं देश की मूल आवश्यकता जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन, जल आदि। राजनेता वंचित हो जाते है जिसका परिणाम मृत्यु दर में वृद्धि स्वास्थ्य में गिरावट, कुपोषण आदि होते है। वैश्वीकरण से इन देशों में एक तबका धनिक वर्ग का काफी ऊँचा उठा है तो वहीं अधिकांश जनता वर्ग की हालत दिन–प्रतिदिन खराब होती गई हैं। अतः वैश्वीकरण विकासशील राष्ट्रों के लिए कम लाभ एवं अधिक नुकसान का सूचक है।

अविकसित देश एवं वैश्वीकरण :–

वैश्वीकरण का प्रभाव अविकसित देशों में कहे तो बहुत घातक हुआ है एक प्रकार से कहा जा सकता है नवसाम्राज्यवाद का शिकार बन जाते है। इन राष्ट्रों के प्रत्येक क्षेत्र में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक प्रत्येक क्षेत्र प्रभावित रहता हैं। एक प्रकार से वैश्वीकरण के एजेन्ट बहुराष्ट्रीय कम्पनियां एवं निगम ये सभी इन राष्ट्रों की लगभग सभी गतिविधियों में शामिल होकर अपने हितों की पूर्ति करते है। अतः देखा जाता है इन राष्ट्रों में राष्ट्रीय एवं सामाजिक एकता का बिखराव हो जाता है।

भारत एवं वैश्वीकरण :–

भारत पर वैश्वीकरण के प्रभाव की बात की जाये तो यह कहना उपयुक्त ही होगा कि भारत जिस प्रकार की धारणा बनाकर बैठा था कि एकाएक कायाकल्प हो जायेगा एवं राष्ट्रीय विकास तीव्र गति से होगा तो ये केवल भ्रम ही था कुछ सीमित लाभ के सिवा इसके परिणाम नकारात्मक ही देखने को मिले। भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित प्रकृति की है यह टाटा, अंबानी, हिन्दुजा, बिरला, डालमिया, सहारा जैसे निजी घराने फले फूले वहीं सार्वजनिक क्षेत्र भी कुछ कम नहीं थे 1990 से 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार द्वारा उदारीकरण एवं निजीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई। एक दशक बाद भी उदारीकरण की प्रक्रिया अपनी पराकाष्ठा को पार कर रही है वैश्वीकरण आज पूर्ण रूप से भारत के राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक प्रत्येक क्षेत्र में पूर्ण रूप से समा गया है। इसका अनुमान हम इस बात से लगा सकते है जहॉ WTO द्वारा भारत को पूर्ण आयात प्रतिबंध 2003 में हटाने थे वहीं भारत द्वारा वैश्वीकरण के प्रति तीव्र उत्कंठा से 2001 में ही यह प्रतिबंध हटा दिये गये। बहुराष्ट्रीय कम्पनियॉ नई आधारिक संरचना स्थापित नहीं करना चाहती है बल्कि भारतीय बहुसंख्यक उपभोक्तावर्ग को देखते हुए उत्पादों में ही व्यय करना चाहती है। बजट निर्धारण भी पूँजीपतियों एवं बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को ध्यान में रखकर ही किया जा रहा है और मूलभूत आवश्यकताओं में दिन–प्रतिदिन सरकारी खर्चो के नाम पर कटौती की जा रही है। घरेलू लघु एवं कुटीर उद्योगों में एक प्रकार का संकट देखने को मिल रहा है। इस प्रकार देखा जाये तो पूँजीपति वर्ग का एक छोटा तबका दिन–प्रतिदिन उभर रहा है वहीं अधिसंख्यक वर्ग इसके नकारात्मक परिणाम झेल रहे है।

निष्कर्ष :–

अतः इस प्रकार स्पष्ट है वैश्वीकरण जहॉ विकसित देशों के पूँजीवादी विचार के अनुकूल पाया गया वहीं विकासशील एवं अविकसित राष्ट्रों के लिए सकारात्मक परिणाम बहुत कम होते हुए नकारात्मक परिणाम अधिक देखे गये है। वैश्वीकरण जिस प्रकार प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित करता है जैसे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, स्पष्टतः कहा जा सकता है कि भारत की विदेश नीति भी कही न कही इसके प्रभाव से अछूती नहीं है और प्रत्येक शासनकाल में परिवर्तन देखे गये है।

सन्दर्भ सूची

1. दुबे कुमार अभय, भारत का भूमंडलीकरण, वाणी प्रकाशन, 2007, पृष्ठ (26, 27, 28, 29, 30)
2. बिस्वाल तपन, अन्तर्राष्ट्रीय संबंध, मैकमिलन प्रकाशन, 2013, पृष्ठ (268, 69, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 88, 89)
3. विकिपीडिया.IN.WWW
4. कश्यप पी0एस0 डॉ0; प्रतियोगिता दपर्ण, अगस्त, 2015, पृष्ठ संख्या–77, 78
5. दत्त एवं सुन्दरम, भारतीय अर्थव्यवस्था, निरजा पब्लिशर्स, 2016 पृष्ठ संख्या–250
6. सिंह पी0 के0, समकालीन राजनीतिक मुद्दे, यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन, 2012, पृष्ठ संख्या–135–37
7. त्रिवेदी, एन0आर0 डॉ0; राय पी0 एम0 डॉ0, भारतीय सरकार एवं राजनीति, अध्याय 47, लक्ष्मी पब्लिसर्स, जयपुर
8. मिश्र के0 एस0/पुरी के0 वी0, भारतीय अर्थव्यवस्था, हिमालय पब्लिशिंग हाउस, पृष्ठ संख्या–616–617